श्री शमशेर सिंह मन्हास: सर, मेरा सवाल कमजोर वर्ग और मॉननॉरिटी के लोगों के संबंध में है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कमज़ोर वर्ग और मॉइनॉरिटी वर्ग के लिए क्या अलग प्रकार से कोई डेटा रिज़व किया जाता है या अलग से बनाने का प्रावधान है?

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Sir, Socio-Economic Caste Census, यह इन्हीं deprivations के आधार पर बना है और इसी का उपयोग स्वास्थ्य मंत्रालय कर रहा है।

Information on black money from Switzerland

*64. SHRI RAM KUMAR KASHYAP: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government's fight against black money has taken a major beating as the latest data released by the Swiss National Bank has revealed that the amount deposited by Indians in the Swiss banks in the past one year has increased by 50 per cent;

(b) whether India and Switzerland have signed an agreement for automatic information exchange and if so, the details thereof;

(c) whether Indian Government has received any information on black money from Switzerland;

(d) if so, the details thereof; and

(e) if not, by which date India will receive information on black money from Switzerland?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PIYUSH GOYAL): (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) No Sir.

The Government has taken various steps in its crusade against black money, including black money stashed abroad, which have led to positive results, including India and Switzerland signing the Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) pursuant to which the Automatic Exchange of Information (AEOI) is activated between the two countries for sharing of financial account information effective from 01.01.2018 with first transmission in 2019. Accordingly, India will receive the information of financial

accounts held by Indian residents in Switzerland for 2018 and subsequent years, on an automatic basis.

Swiss authorities have shared the following information regarding the Swiss National Bank (SNB) figures quoted in the media "The figures published by the SNB are regularly mentioned in the Indian media as a reliable indicator of the amount of assets held with Swiss financial institutions in respect of Indian residents. More often than not, the media reports have not taken account of the way the figures have to be interpreted, which has resulted in misleading headlines and analyses. Moreover, it is frequently assumed that any assets held by Indian residents in Switzerland are undeclared (so-called 'Black Money').

Further they have said "To analyze Indian residents' deposits held in Switzerland, another data source should be used. This is the so-called "locational banking statistics", which the SNB collects in collaboration with the Bank for International Settlements (BIS).

The data collected by Swiss National Bank in collaboration with Bank for International Settlements (BIS) shows that the loans and deposits of Indians, other than Banks, in the Swiss banks decreased by 34.5% in the year 2017 as compared to 2016. Further, there has been significant reduction in Swiss non-bank loans and deposits of Indians by 80.2% between 2013 and 2017.

(b) to (e) India and Switzerland have a Double Taxation Avoidance Agreement in place which entered into force on 29th December, 1994. A Protocol amending the agreement entered into force or. 7th October, 2011. Based on the provisions of Double Taxation Avoidance Agreement, the two countries exchange information on black money covered by the Agreement, on request basis, which is foreseeably relevant to the administration for enforcement of the domestic laws concerning taxes. The information received is utilized to conclude investigations and tax the unaccounted income and assets of the taxpayers, and initiate penalty and prosecution proceedings as applicable.

The Automatic Exchange of Information based on Common Reporting Standard has also commenced from 2017 with many countries enabling India to receive financial account information of Indian residents. This will also be useful in bringing the unaccounted income and assets to tax.

The disclosure of information received under a tax treaty is governed by the confidentiality provisions of the treaty. Further, the disclosure of information in case of individual assesses is protected as per the provisions of Section 138 of the Income-tax Act, 1961.

श्री राम कुमार कश्यपः सर, स्विस बैंकों में भारतीयों का बढ़ता हुए काला धन चिंता का विषय है। मोदी जी की सरकार के आने के बाद यह विश्वास था कि बाहर के देशों में काले धन में कमी आएगी। काले धन को समाप्त करने के लिए चरणबद्ध कार्य होगा, सरकारी एजेन्सियां कुछ ज्यादा काम कर पाएंगी। 2014 से लेकर 2016 तक काले धन में कमी तो आई थी, परन्तु स्विस बैंक के हाल में जारी आंकड़ों के अनुसार ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापतिः आपका क्वेश्चन प्लीज़।

श्री राम कुमार कश्यपः सर, मैं उसी पर आ रहा हूं। भारतीय नागरिकों के जमा धन में, जो 2016 के आंकड़े हैं, उनकी तुलना में 2017 में 50 परसेन्ट से भी ज्यादा वृद्धि हुई है। सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो 2017 में अचानक 50 परसेंट की वृद्धि हुई है, उसके पीछे क्या कारण है?

श्री पीयूष गोयलः माननीय सभापति जी, यह एक और उदाहरण है कि कैसे बेबुनियाद खबर पर कई बार देश की जनता और इतने वरिष्ठ सांसदगण भी ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापतिः उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। Please, please.

श्री सुखेन्दु शेखर रायः सर, माननीय मंत्री जी आरोप लगा रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...

SHRI B.K. HARIPRASAD: Sir. ...*(Interruptions)*...

PROF. M.V. RAJEEV GOWDA: Sir, ...*(Interruptions)*...

SHRI DEREK O'BRIEN: What is this? ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: He has not taken anybody's name. ...*(Interruptions)*...

SHRI DEREK O'BRIEN: What is this? ...*(Interruptions)*...

श्री पीयुष गोयलः सर, इस देश के बड़े-बड़े नेता और वरिष्ठ सांसदगण भी ...**(व्यवधान)**... ऐनेलाइज़ नहीं कर सकते हैं और समझ नहीं पाते हैं। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: He has not taken anybody's name. ...*(Interruptions)*...

SHRI DEREK O'BRIEN: What is this? ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please he has not taken any name.

श्री पीयूष गोयलः माननीय प्रधानमंत्री जी सरकार 2014 के आने के बाद ...**(व्यवधान)**... एक के बाद एक लगातार काले धन के ऊपर इस सरकार के द्वारा जो प्रहार किया है, उसी के कारण स्विस बैंकों में भी जो पैसा या धनराशि रखी थी, वह 2014 से 2017 के अंत तक 80 प्रतिशत घटी है। यह statistics पूरे देश के समक्ष है। अब मैं आता हूं उस statistics के ऊपर जिसे माननीय सांसद जी ने refer किया है। मैं उनका एक statistics के ऊपर ध्यान आकर्षित करूंगा। स्विस नेशनल बैंक ने डेटा निकाला कि विश्व भर में स्विस बैंकों में जो कुल राशि है, उसका ऐनेलिसिस करके उन्होंने एक डेटा निकाला, हो सकता है कि वह स्विस बैंक का खाता भारत की किसी ब्रांस में भी हो, हो सकता है वह विश्व भर में कहीं भी, किसी भी भारतीय का हो, चाहे वह भारत में रहता है चाहे Non-Resident Indian हो। अलग-अलग प्रकार से, ये पैसे स्विस बैंक में कोई भी वैध-अवैध रखे, वह सारा डेटा कंपाइल करके स्विस नेशनल बैंक एक फिगर निकालता है। मैंने स्विस अथॉरिटीज़ से चर्चा की कि यह क्या है, What is this figure? इसमें मुझे लिखित जवाब आया और मैं quote करना चाहूंगा। स्विस नेशनल बैंक का फिगर मीडिया में आया है, उसके बारे में स्विस अथॉरिटीज़ कहती है, "The figures published by the SNB, the Swiss National Bank, are regularly mentioned in the Indian media as a reliable indicator of the amount of assets held with Swiss financial institutions in respect of Indian residents." Then, he clarifies की यह कैसे गलत है, He says, "More often than not, the media reports have not taken into account the way the figures have to be interpreted, which has resulted in misleading headlines and analysis." यह सरकारी response है।

MR. CHAIRMAN: Right, Now, second supplementary.

श्री पीयूष गोयलः सर, एक ही मिनट लूंगा। "Moreover, it is frequently assumed that any assets held by Indian residents in Switzerland are undeclatred (so-called 'Black Money')."

फिर उनका कहना है कि अगर आप को सच में इंडियन रेसिडेंट्स का कितना पैसा स्विट्जरलैंड में है, वह देखना है तो जो एक राइट डेटा सोर्स है, वह स्विस अथॉरिटीज़ कह रही है, जो करेक्ट डेटा सोर्स है, उसको कहते हैं - locational banking statistics, कि लोकेशन स्विट्ज़रलैंड में

[श्री पीयूष गोयल]

है। कितना पैसा है, यह भी स्विस नेशनल बैंक collect करता है, in collaboration with the Bank for International Settlements. माननीय सभापति महोदय, उस डेटा के अनुसार...

श्री सभापतिः आप संक्षेप में बोलिए।

श्री पीयूष गोयलः माननीय सभापति महोदय, यह बड़ा important विषय है, ज्वलंत विषय है।

श्री सभापतिः ठीक है।

श्री पीयूष गोयलः देश के लोगों के गलतफहमियां दूर करने की जिम्मेदारी सरकार की है। खुद स्विस अथॉरिटीज़ लिखित रूप में देती हैं कि Swiss National Bank, in collaboration with Bank for International Settlement का जो डेटा है, वह दर्शाता है कि loans and deposits of Indians– other than banks; मतलब RBI भी रख सकता है, स्टेट बैंक भी रख सकता है। बैंकों को छोड़ो; जो individuals के deposits स्विस बैंक में स्विटज़रलैंड में हैं – decreased by 34.5 per cent in the last year compared to the previous year.

MR. CHAIRMAN: Right. Second supplementary.

श्री पीयूष गोयलः 34.5 परसेंट कम हुआ और आखिरी क्वार्टर में तो 44 परसेंट कम हुआ।

MR. CHAIRMAN: No, no, please ...*(Interruptions)*... Please. ...*(Interruptions)*... Mr. Minister, please confine to the issue.

श्री राम कुमार कश्यपः सभापति महोदय, स्विस बैंक ने जब यह रिपोर्ट जारी की है कि स्विस बैंक में भारतीय नागरिकों की जमा राशि 2016 के आंकड़ों की तुलना में 2017 में 50 परसेंट से भी ज्यादा बढ़ गयी है, तो माननीय पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने अपने ब्लॉग पर लिखा है कि स्विस बैंकों ने जो आंकड़ें सार्वजनिक किए हैं, उनमें सब काला धन नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अगर वह सारा काला धन नहीं है, तो उसमें से कितना काला धन है और यह काला धन कब तक भारत आएगा?

श्री पीयूष गोयलः सभापति जी, माननीय सांसद जी भली-भांति जानते हैं कि वर्ष 2011 में केन्द्रीय सरकार ने, माननीय पूर्व प्रधान मंत्री जी भी यहां पर हैं, स्विस बैंक के साथ ट्रीटी अमेंड की थी कि जब भी हमारे पास कोई information आएगी, तो हम उसके बारे में उनसे जानकारियां ले सकते हें। दुर्भाग्य से 2011 से 2014 के बीच कई HSBC के अकाउंट्स वगैरह की जानकारियां आयीं, जिनके बारे में हम

स्विटज़रलैंड से जानकारियां मांगते रहे, लेकिन information नहीं मिली। फिर, अक्टूबर, 2014 में प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने रेवेन्यू सेक्रेटरी और अधिकारियों को वहां पर भेजा और सख्ती से वहां पर बात करने के बाद ज्वाइंट मैकेनिज्म इश्यू हुआ कि आगे से वे हमें information देने में मदद करेंगे। सभी माननीय सांसद यह जानकार खुश होंगे कि 2014 के बाद लगभग चार हजार से अधिक information हमने वहां से मांगी हैं और उस डेटा के ऊपर सचिव कार्रवाई देश में हो रही है।

इसी के साथ-साथ, अभी हमने जो नई ट्रीटी स्विट्ज़रलैंड के साथ रीनेगोशिएट की है, उसके तहत 1 जनवरी, 2018 के बाद किसी भी भारतीय नागरिक के द्वारा जो भी transactions स्विट्ज़रलैंड में होंगे, उसको हमें मांगना भी नहीं पड़ेगा, उसका automatic data भारत को मिल जाएगा ...**(व्यवधान)**... जिसके आधार पर हम कार्रवाई कर सकते हैं। ...**(व्यवधान)**... यह भी दिसम्बर, 2017 का डेटा है। उसके opening balance के रूप में हमें automatically सब जानकारियां मिल जाएंगी।

श्री सभापतिः ठीक है। श्री सुखेन्दु शेखर राय।

श्री देरेक ओब्राईनः बोलो दादा। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापतिः प्लीज़। ऐसे नारा देने से क्या होगा? वहां तक पहुंचेगा नहीं, स्विस बहुत दूर है।

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: Sir, it appears from the reply given by the hon. Minister that the Double Taxation Avoidance Agreement was executed on 29th of December, 1994. Then Protocol, amending the Agreement, entered into on 7th of October, 2011 and the Multilateral Competent Authority Agreement was executed on 1st of January, 2018. So, since last 24 years or so, the Agreements are being executed. I want a specific reply from the hon. Minister that how much unaccounted deposit of Indians have so far been recovered from Switzerland, in how many cases prosecution proceeding has been initiated and when the citizens of India will get Rs. 15 lakhs in their account.

SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, I think, the hon. Member may have some information which the Government does not have. If he is privy to any information about black money, I think he should put it before the Government so that the Government can take action. ...*(Interruptions)*...

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: Sir, he is casting an aspersion. ...*(Interruptions)*... The Minister cannot cast aspersion. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: You answer the question. ...*(Interruptions)*...

SHRI PIYUSH GOYAL: How has the Government got any data ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: You just answer the question, please. ...*(Interruptions)*... I told him. ...*(Interruptions)*... He will answer the question. ...*(Interruptions)*... Please, please. ...*(Interruptions)*...

SHRI PIYUSH GOYAL: In the last four financial years, from 2014 to 2018, the Government has sought 4843 exchange of information requests. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: I have already told him. He has to answer the question. That's all. Nothing else. ...*(Interruptions)*... Please. ...*(Interruptions)*...

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: Sir, he is casting aspersion. ...*(Interruptions)*... He must withdraw it. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: No aspersion. ...*(Interruptions)*...

SHRI PIYUSH GOPAL: Sir, I did not cast aspersion. ...*(Interruptions)*... I made an appeal, through you, that if he has any information, he should give it to the Government. ..*(Interruptions)*... How is that an aspersion? ...(*(Interruptions)*... How is that an aspersion? ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*... He has clarified it. ...*(Interruptions)*... He has clarified it. ...*(Interruptions)*...

SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, I am making an appeal to the hon. Member that if he has any information, he should give it to us. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: He has clarified that he has not cast any aspersions. That is the end of it. ...*(Interruptions)*... The Question Hour goes! ...*(Interruptions)*...

SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, as regards information on requests for exchange of information, the Government has made 4843 exchange of information requests to foreign jurisdictions in the last four financial years, and the proceedings are going on. ...*(Interruptions)*...